

स्पेक्ट्रम की नीलामी अब 25 जून को

नई दिली (ईएमएस)। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा 19 दिन बढ़ा दी है यह नीलामी अब 25 जून होगी। विभाग की बेसाइट पर यह जानकारी मिलती है। नीलामी के लिए आवेदन अप्रैलिन करने वाले नोटिस में किए गए संशोधन के मुताबिक कि लाइव नीलामी की शुरुआत की नई तारीख 6 जून से बदलते कर 25 जून कर दी गई है। सरकार मोबाइल फोन सेवाएं के लिए करीब 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। नीलामी में 800 मेगाहर्ड्स, 900 मेगाहर्ड्स, 1800 मेगाहर्ड्स, 2100 मेगाहर्ड्स, 2300 मेगाहर्ड्स, 2500 मेगाहर्ड्स और 26 मेगाहर्ड्स और 26 मेगाहर्ड्स बैंड में उपलब्ध हैं।

रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए की संख्या ज्ञाना राशि जमा की है। इसे कंपनी मैक्सिमम रेडियो जीसी बैंडोंसी के लिए बोली लगा सकती। बोली लगाने के लिए पूर्ण पात्रता विवरण के मुताबिक भारती एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और बोडफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा कर दी है।

भारत की सर्विस सेक्टर की ग्रोथ घटकर निचले स्तर पर आई

नई दिली (ईएमएस)। भीषण गर्भी, कड़ी प्रतिस्पर्धा, मूल्य दबाव के चलते मई माह में भारत के सेवा बाजार की बृद्धि दर घटकर निचले स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नए ढेकों में एक दशक में सबसे तेज बृद्धि दर्ज की गई। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई।

पीसीसी रूप से समायोजित एच एसीसी इंडिया भारत सेवा वीएसआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक मई माह में गिरकर 60.2 पर आ गया जो पिछले साल दिवंगर के बाद से सबसे निचला स्तर पर था। खाड़ी प्रबंधक सूचकांक (पीएसआई) की भाषा में 20.8 पर था खाड़ी प्रबंधक सूचकांक समायोजित मिला है। प्रस्तुत बृद्धि में सक्षमता रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बृद्धि की भाव चढ़ गए। चांदी की शुरुआत मिले जाएं ही। उसको बृद्धि अर्थात् दास ने कहा कि मई में भारत की सेवा गतिविधि थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ी, घेरने नए ढेकों में थोड़ी जीवी अंदर लेनिंग वे बढ़ाव बढ़ाव रखे। यह भजबूत मांग को दर्शाता है।

उद्देश्य के मुताबिक एक और सकारात्मक बात यह है कि कारोबारी विश्वास में 8 महीनों में सबसे ज्यादा

अब नई सरकार को जीएसटी, महंगाई जैसे मुद्दों का करना होगा सामना

-आम जनता को बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात पाने की आस

नई दिली (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं अब देश को नई सरकार बनने का उंतजार है और कई कई आशाएं भी हैं। आम जनता नई सरकार से महाराष्ट्र, बोरोजगारी जैसे समस्याओं से निजात पाने की आस लगाए हैं। वहीं दोनों में नई सरकार के सामने कई प्रमुख नीतियां मुद्दों होंगी। इन मुद्दों में जीएसटी में सुधार, महंगाई, सार्वजनिक वित्त, खाद्य कीमतें और निवेश को बढ़ाव देना आदि कई कई शामिल हैं। नई सरकार को कई उचित होगी।

नई सरकार को पहले भू-राजीनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण सुधारों में तेजी लाने की जरूरत होगी, लेकिन केंद्र ने गवर्नेंट बैंडों की सरकार होने से यह आसान ही नहीं होगी। नीतियां और जीएसटी पर नवीनियां जैसे मुद्दों पर आम सहमति की जरूरत होती है। जिस पर नई सरकार को ध्यान देने की उम्मीद है।

खाद्य स्टॉक बाजार जैसी अस्थिर और उच्च बीमी देखी हैं। नई सरकार कीमतों को मौसम से बदलाने और गर्मी और बाढ़ जैसे जलवायु-प्रेरित झटकों से बदलाने के लिए एक दूसरी बीमी पर आम वाले जीएसटी रेट

स्ट्रेटर का तुरंत रीयू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए 12 फीसदी और 1.8 फीसदी स्ट्रॉबैट मर्ज करने की जरूरत पड़ी, जिससे हाई बैंड के लिए एक दूसरी बीमी देखी जाती है। अगर नई सरकार ने आम वाले जीएसटी को ध्यान देने की उम्मीद है।

पांच स्टॉक बाजार जैसी अस्थिर और उच्च बीमी देखी हैं। नई सरकार कीमतों को मौसम से बदलाने और गर्मी और बाढ़ जैसे जलवायु-प्रेरित झटकों से बदलाने के लिए एक दूसरी बीमी पर आम वाले जीएसटी रेट

स्ट्रेटर का तुरंत रीयू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए 1.8 फीसदी की स्थापना की जरूरत होती है। अंदरूनीय निवाया की शाखाएं पर आम वाले जीएसटी को ध्यान देने की उम्मीद है।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे सेवाल एयरलाइन्स देश छोड़ने को मजबूर! -टेस्ला के सीईओ मस्क ने भी भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना है कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी को ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बाद सरकार ने अपनी एकी पॉलीटैक में बदलाव करके टेस्ला के भारत को एक नया सालाना वार्षिक विवरण के लिए अलावित करने वाली एयरलाइन कंपनियों के इकाईजेट इंडिया की बैंड।

एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएटी के डायरेक्टर जनरल विली चॉला ने कहा कि भारत में टैक्स से जुड़ी वैसी समस्याएं हैं जिनके कारण विवरणीय कंपनियों भारत छोड़ दें।

नई दिली (ईएमएस)। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टैक्स और डबल टैक्सेशन का जीसियम है। ये ऐसे इश्यू हैं एसोसिएशन (आईएटी) ने जेटवाली दी है कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना एक बड़ी भौगोलिक विवरणीय कंपनियों को ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर निवाया की शाखाएं पर आम वाले जीएसटी को ध्यान देने की उम्मीद है।

नई दिली (ईएमएस)। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टैक्स और डबल टैक्सेशन का जीसियम है। ये ऐसे इश्यू हैं एसोसिएशन (आईएटी) ने जेटवाली दी है कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के द्वारा हो गई।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ साल पहले भारत की टैक्स व्यवस्था पर उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में टैक्स की दूसरी व्यवस्था पर आम वाले जीएसटी की स्थापना 1945 में कुछ एयरलाइन कंपनियों के

